



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]  
No. 138]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2008/चैत्र 20, 1930  
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2008/CHAITRA 20, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2008

अंतिम जांच परिणाम

(न्यू शिपर समीक्षा)

विषय : मै. जूनमा टायर कॉड कं. लि., चीन जन. गण. द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार नॉयलोन टायर कॉड फैब्रिक्स (एनटीसीएफ) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की न्यू शिपर समीक्षा (पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत)

सं. 15/11/2006-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया

2. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी को अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए दिनांक 9-3-2005 की अधिसूचना सं. 14/20/2003-डीजीएडी की समीक्षा हेतु उपर्युक्त नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत मै. जूनमा टायर कॉड कं. लि., चीन जन. गण. (जिसे आगे न्यू शिपर कहा गया है) से एक अनुरोध प्राप्त हुआ। आवेदक ने इस आशय के घोषणा पत्र प्रस्तुत किए कि वे संबंधित उत्पाद के बारे में लागू पाटनरोधी उपाय में चीन जन. गण. के किसी भी निर्यातक और उत्पादक से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह घोषणा की कि उन्होंने मूल जांच की जांच अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की और उसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के उपबंधों के अनुसार समीक्षा की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त माना।

- (ii) प्राधिकारी ने दिनांक 11.7.2006 की अधिसूचना सं.15/11/2006-डीजीएडी, के तहत पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत मै. जूनमा टायर कॉड कं. लि., चीन जन.गण.(उत्पादक एवं निर्यातक) द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर न्यू शिपर समीक्षा शुरू की ।
- (iii) उपर्युक्त न्यू शिपर समीक्षा चीन जन.गण. मूल के या वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 59 के अंतर्गत आने वाले नायलॉन टायर कॉड फैब्रिक्स (एनटीसीएफ) के आयात के मामले में शुरू की गई थी जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी दिनांक 9.3.2005 के अंतिम जांच परिणाम सं.14/20/2003-डीजीएडी के तहत इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि:
- (क) संबद्ध देश के मूल के या वहां से निर्यातित सभी प्रकार के एनटीसीएफ का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;
- (ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- (ग) वास्तविक क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है ।
- (iv) केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 59 के अंतर्गत आने वाले चीन जन.गण. से नायलान टायर कॉड फैब्रिक्स (एनटीसीएफ) के आयातों पर दिनांक 27.4.2005 की अधिसूचना सं. 36/2005-सीशु. के तहत मूल जांच में पाटनरोधी शुल्क लगाया था;
- (v) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार और दिनांक 27.4.2005 के अधिसूचना सं. 36/2005-सीशु. को ध्यान में रखते हुए न्यू शिपर समीक्षा पूर्ण होने तक मै. जूनमा टायर कॉड कं. लि., चीन जन.गण.(उत्पादक एवं निर्यातक) द्वारा किए गए नायलान टायर कॉड फैब्रिक्स (एनटीसीएफ) के सभी निर्यातों के अनंतिम निर्धारण की सिफारिश की;
- (vi) वित्त मंत्रालय ने 29 अगस्त, 2006 को अधिसूचना सं. 84/2006-सीशु.जारी की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा परिणाम निकाले जाने तक मै. जूनमा टायर कॉड कं. लि., चीन जन.गण.द्वारा उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्ष 590210 के अंतर्गत आने वाले नायलान टायर कॉड फैब्रिक्स (एनटीसीएफ) का जब भारत में आयात किया जाएगा, तो उसका समीक्षा पूरी होने तक अनंतिम निर्धारण किया जाएगा । आगे यह प्रावधान किया गया था कि अनंतिम निर्धारण प्रतिभूति या गारंटी के अधीन हा सकता है, जैसा कि सीमाशुल्क का उचित अधिकारी कमी, यदि कोई हो, के भुगतान हेतु उचित समझे, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच पूरी करने के बाद भूतलक्षी प्रभाव से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उक्त समीक्षा पूरी करने के बाद पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश

किए जाने की स्थिति में आयातक को उक्त समीक्षा की शुरुआत की तारीख से मै. जूनमा टायर कॉड कं. लि., चीन जन.गण. द्वारा निर्यातित और भारत में आयातित भारत में सबद्ध वस्तु के सभी आयातों की समीक्षा के उपरांत संस्तुत ऐसे शुल्क की राशि का भुगतान करना होगा जिसे ऐसे आयातों पर लगाया जाएगा ।

- (vii) प्राधिकारी ने मै. जूनमा टायर कॉड कं. लि., चीन जन.गण.(उत्पादक एवं निर्यातक) को निर्यातक प्रश्नावली तथा बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार (एमईटी) संबंधी प्रश्नावली की एक प्रति भेजी । प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सूचना मांगी । प्राधिकारी ने मै. जूनमा टायर कॉड कं. लि., चीन जन.गण.(उत्पादक एवं निर्यातक) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का उनके परिसरों में सत्यापन किया ।
- (viii) इस न्यू शिपर जांच में जांच की अवधि पाटन के निर्धारण हेत 12 माह अर्थात् 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक की है ।
- (ix) प्राधिकारी ने न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत के बारे में निर्यातक देश के प्राधिकारी को सरकारी तौर पर सूचित किया और संबंधित सभी हितबद्ध पार्टियों को 11.7.2006 की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 40 दिन के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।
- (x) प्राधिकारी ने 30.11.2006 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाली सभी पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था ।
- (xi) नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने अनुरोध करने पर सभी हितबद्ध पार्टियों को सार्वजनिक फाइल निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जिसमें विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं ।
- (xii) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 क अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार का खुलासा ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष किया गया और उस पर प्राप्त टिप्पणियों पर भी इन जांच परिणामों में विधिवत विचार किया गया है ।
- (xiii) \*\*\* यह चिन्ह हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने उसे नियमानुसार गोपनीय ही माना है । आवेदक द्वारा कीमत और लागत के बारे में प्रस्तुत सूचना को गोपनीय होने का दावा किया गया था और इसे प्राधिकारी ने गोपनीय माना था ;

## ख. विचाराधीन उत्पाद

3. चूंकि यह नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु एक समीक्षा है इसलिए 8.3.2005 की मूल जांच सं. 14/20/2003-डीजीएडी में उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद वही बना रहेगा। किसी भी हितबद्ध पार्टी ने इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है। मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद का उल्लेख जांच परिणामों के पैरा 3 में निम्नानुसार किया गया है:-

"वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य के मूल का या वहां से निर्यातित नायलान टायर कॉड फैब्रिक (एनटीसीएफ)। संबद्ध वस्तु नायलान का एक फैब्रिक है जो मुख्यतः टायर कॉड के लिए होता है। एनटीसीएफ का उपयोग बस और ट्रक के टायरों, दुपहिया वाहनों के टायरों, साइकिल टायरों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों के टायरों, पशु चालित वाहनों आदि जैसे विभिन्न प्रकार के आटोमोटिव टायरों में किया जाता है।

नायलान टायर कॉड फैब्रिक का उत्पादन धागे के विभिन्न डेनियरों के उपयोग से किया जाता है। फैब्रिक का उपयोग टायरों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। उत्पाद की बिक्री "ग्रे फैब्रिक" और "डिप्ड फैब्रिक" के रूप में भी की जाती है। भारतीय टायर उद्योग द्वारा ग्रे और डिप्ड दोनों फैब्रिकों की खरीद की जा रही है। साइकिल टायर विनिर्माताओं को बेचा जा रहा डिप्ड फैब्रिक का याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेख "साइकिल टायर फैब्रिक" के रूप में किया जाता है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि साइकिल टायर फैब्रिक भी डिप्ड फैब्रिक के सिवाय कुछ नहीं है। यद्यपि, साइकिल टायर विनिर्माताओं से भिन्न टायर उत्पादकों को बेचे जा रहे अन्य डिप्ड फैब्रिक की तुलना में उसकी लागत और कीमत कुछ अधिक होती है। साइकिल टायर के उपयोग हेतु निर्दिष्ट डिप्ड फैब्रिक का उल्लेख इस अधिसूचना में साइकिल टायर फैब्रिक (सीटीसी) और सभी अन्य डिप्ड फैब्रिक का उल्लेख "डिप्ड फैब्रिक" के रूप में किया गया है। श्रेणीकरण पर ध्यान न देते हुए एनटीसीएफ का टैरिफ वर्गीकरण दोनों के लिए एक समान है। सभी प्रकार का एनटीसीएफ विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है और इसे अध्याय 59, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, के सीमाशुल्क उप शीर्ष सं. 5902.10.00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।"

4. न्यू शिपर ने यह उल्लेख किया है कि उन्होंने ग्रीज और डिप्ड प्रकार के एनटीसीएफ का निर्यात किया है। रिकार्ड से यह नोट किया गया था कि न्यू शिपर ने मुख्यतः एनटीसीएफ ग्रीज का 91% और शेष 9% एनटीसीएफ डिप्ड का निर्यात किया है।

## ग. अन्य मुद्दे :

### ग.1 सामान्य मूल्य का मुद्दा:

5. भारतीय निर्यातकों ने मै.एसआरएफ लि., मै. सेंचुरी एंका लि. तथा मै. एनआरसी लि. की ओर से यह उल्लेख किया है कि मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [(2006(202)ईएलटी 23 (एससी)] के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते

हुए यह जांच वर्तमान रूप में और ढंग से आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सामान्य मूल्य देश विशिष्ट होता है और उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सामान्य मूल्य निर्यातक के लिए नहीं होगा ।

6. इस संबंध में न्यू शिपर ने यह उल्लेख किया है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण जांचाधीन निर्यातक या उत्पादक द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर करना होता है । इस जांच में न्यू शिपर जांचाधीन निर्यातक है । यह भी अनुरोध किया गया है कि संविधियों के अर्थनिरूपण संबंधी विधि शास्त्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि विधान के प्राथमिक उद्देश्य का पता प्रयोग की गई भाषा से लगाना होता है; इस प्रकार यह कहना कि जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, संविधि की सीधी-सादी भाषा को उपयोग में लाया जाना चाहिए ।

7. प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की है और यह नोट करते हैं कि मै. एच एंड आर जानसन (इंडिया) लि. बनाम वित्त मंत्रालय एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टेट ने अपील सं. 2007 की 01 में दिनांक 27.8.2007 के आदेश में यह अभिमत व्यक्त किया है कि सामान्य मूल्य के बारे में उच्चतम न्यायालय का अभिमत "नियम 22 के उपबंधों की स्कीम पर लागू नहीं होता है जिसमें न्यू शिपर के अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करना अपेक्षित है"। सेस्टेट के अभिमत को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर समीक्षा के संदर्भ में सामान्य मूल्य के बारे में घरेलू उद्योग का तर्क वैध नहीं है ।

## ग.2 न्यू शिपर के रूप में जूनमा की अर्हता

8. मै. एसआरएफ लिमिटेड, मै. सेंचुरी एंका लिमिटेड और मै. एनआरसी लिमिटेड की ओर से भारतीय उत्पादकों ने अनुरोध किए हैं ।

9. यह अनुरोध किया गया है कि न्यू शिपर के रूप में जूनमा के पास अर्हता नहीं है क्योंकि कंपनी ने ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि कंपनी न्यू शिपर के रूप में अर्हता रखती है । इस संबंध में याचिका से जो पता चलता है वह मात्र कंपनी की ओर से किया गया दावा है । तथापि, आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई समर्थकारी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

10. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को भी ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान आवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जा रही अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है । कंपनी ने केवल प्राधिकार पत्र, कंपनी का कारोबार लाइसेंस, वर्ष 2005 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, कंपनी की पुस्तिका और मूल जांच में जांच अवधि के दौरान "कोई निर्यात" न करने की घोषणा दायर की है । यह सूचना इस बात की पुष्टि करने का कोई साक्ष्य नहीं हो सकती है कि उन्होंने पूर्ववर्ती जांच अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया था । यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदन में उत्पादन सुविधाओं से संबंधित सूचना छिपाई गई है ।

11. यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय उत्पादक यह समझते हैं कि जूनमा ने जांच अवधि के दौरान या उससे पूर्व भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया था । तथापि, जूनमा ने न तो मूल जांच के समय और न ही वर्तमान आवेदन में इन निर्यातों का कोई ब्यौरा उपलब्ध कराया है । इस प्रकार यद्यपि यह कंपनी पूर्ववर्ती जांच में असहयोगी रही थी, तथापि इस कंपनी ने वर्तमान आवेदन में अपर्याप्त/अधूरी सूचना प्रस्तुत की है ।

12. यह भी उल्लेख किया गया है कि जब तक उत्पादन या बिक्री या उससे जुड़े कार्यकलाप में शामिल सभी कंपनियां निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं देती हैं, तब तक जांच जारी नहीं रखी जा सकती।

### न्यू शिपर द्वारा किए गए अनुरोध

13. यह अनुरोध किया गया है कि न्यू शिपर ने निगमन प्रमाण पत्र दायर किया है, जिसमें कारोबार शुरू करने की तारीख का उल्लेख है। न्यू शिपर की शुरुआत की मंशा को प्राधिकारी ने दर्ज किया है और कंपनी के नाम में परिवर्तन का उल्लेख किया है। संबद्ध वस्तु के निर्यात मूल जांच में निर्धारित जांच अवधि से पूर्णतः बाहर थे। प्रश्नावली के अपने उत्तर में आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उनकी संबंधित उत्पाद के उत्पादन या बिक्री में लगी कोई संबद्ध/संबंधित कंपनी नहीं है जिन पर पूर्व में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया हो। यह भी अनुरोध किया गया है कि न्यू शिपर ने जांच शुरू करने से पूर्व प्राधिकारी के सभी प्रश्नों/स्पष्टीकरणों का स्पष्ट उत्तर दिया है। प्राधिकारी ने इन मुद्दों पर गौर किया है और उसने लागू नियमों तथा प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अपनाई गई पद्धति के भीतर जांच की सही शुरुआत की है।

14. संबंधित प्रत्येक कंपनी से पृथक प्रश्नावलियों के उत्तर के मुद्दे के संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन या बिक्री में शामिल कोई संबंधित पार्टी या ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके पास उजरती कार्य की व्यवस्था हो, अतः पृथक प्रश्नावलियों के उत्तर दायर करने का प्रश्न नहीं उठता है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

15. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए न्यू शिपर समीक्षा शुरू की जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

- (क) "नियम 22: (1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रश्नाधीन निर्यातक देश के ऐसे किन्हीं निर्यातकों या उत्पादकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करेंगे, जिन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है बशर्ते ये निर्यातक या उत्पादक यह प्रदर्शित करें कि वे निर्यातक देश के ऐसे किन्हीं निर्यातकों या उत्पादकों से संबंधित नहीं हैं, जिनके उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।
- (ख) केन्द्र सरकार इस नियम के उपनियम (1) में उल्लिखित समीक्षा अवधि के दौरान ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों से हुए इयातों पर अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाएगी;
- (ग) परंतु केन्द्र सरकार उस स्थिति में अनंतिम निर्धारण का सहारा ले सकती है और आयातक से गारंटी की मांग कर सकती है यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस प्रकार की सिफारिश की हो और यदि ऐसी किसी समीक्षा की परिणति ऐसे उत्पादकों या निर्यातकों के संबंध में पाटन के निर्धारण के रूप में होती है तो वह समीक्षा की

शुरूआत की तारीख से ऐसे मामलों में भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क की वसूली कर सकती है ।"

16. नियम 22 में उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है जिनमें अलग-अलग पाटन मार्जिन की गणना के प्रयोजनार्थ कोई न्यू शिपर जांच की जा सकती है । प्रश्नाधीन निर्यातक देश के किसी निर्यातक या उत्पादक के संबंध में अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है बशर्ते निम्नलिखित दो शर्तें पूरी हो जाती हों;

- (क) कि निर्यातक या उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है; और
- (ख) कि निर्यातक या उत्पादक यह प्रदर्शित करता है कि वह निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं है जिसके संबंधित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है ।

17. वर्तमान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर यह पाया है कि निर्यातक या उत्पादक ने मूल जांच में जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है और इस आशय का प्रमाणन उपलब्ध कराया है कि वे निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं हैं, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है । जांच शुरू करने से पूर्व प्राधिकारी ने संस्था के अंतर्नियमों तथा वार्षिक रिपोर्टों आदि जैसे दस्तावेज मांगे जिनसे अन्य कंपनियों के साथ आवेदक के संबंध तथा किए गए निर्यातों का खुलासा हो सके ताकि घोषणा की सत्यता की जांच की जा सके । जांच के समय प्राधिकारी को ऐसा कोई साक्ष्य/सूचना प्राप्त नहीं हुई जिनसे इस बात का पता चले कि आवेदक द्वारा दायर घोषणाएं झूठी हैं । किसी विश्वसनीय सूचना के अभाव में आवेदक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निहितार्थ नहीं लगाया जा सकता ।

18. जांच के दौरान प्राधिकारी ने न तो चीन जन.गण. में ऐसे किसी निर्यातक और उत्पादक, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा हो, के साथ संबंध का कोई साक्ष्य पाया और न ही इस संबंध में कोई वास्तविक साक्ष्य किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा प्राधिकारी के समक्ष लाया गया था । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि न्यू शिपर समीक्षा जांच की शुरूआत और उसका निष्पादन पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में निर्धारित उपबंधों के अनुसार किया गया था जो डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के अनुरूप है ।

#### घ. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे

19. मै. एसआरएफ लि. मै. सेंचुरी एंका लिमिटेड तथा मै. एनआरसी लिमिटेड की ओर से भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए अनुरोध

क. जिन कंपनियों के उत्पाद का भारत को निर्यात किया गया है, उसके उत्पादन में संलग्न सभी कंपनियां निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष नहीं आई हैं ।

- ख. एनटीसीएफ के उत्पादन हेतु सभी संयंत्रों का स्वामित्व और उन पर नियंत्रण चीन सरकार के पास है। राज्य के स्वामित्व/नियंत्रण वाले इन संयंत्रों को कुछ मामलों में पूर्ण रूप से तथा अन्य मामलों में आंशिक रूप से निजी कंपनियों ने अधिग्रहीत कर लिया है। ऐसा मामला होने के कारण आवेदक द्वारा इस बात की पुष्टि करना अपेक्षित है कि निजी पार्टियों को ऐसे संयंत्रों के स्वामित्व का हस्तांतरण बाजार कीमत पर किया गया है और ये पूर्ववर्ती गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से प्रभावित नहीं है।
- ग. आवेदक की एक ऐसी संबंधित कंपनी है जो कंपनी को विद्युत की आपूर्ति करती है लेकिन निर्यातक के उत्तर में इस बात का खुलासा किया गया प्रतीत होता है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा अन्य संबंधित कंपनियों से विचाराधीन उत्पाद और निविष्टियों की भी खरीद की जा रही है जिनके ब्यौरों का प्रकटन निर्दिष्ट प्राधिकारी को नहीं किया गया है।
- घ. भारतीय उत्पादकों ने अनुरोध किया है कि राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी झेंगजियागेंग नायलोन टायर कॉड फैक्ट्री द्वारा अब भी टायर कॉड फैब्रिक का उत्पादन किया जा रहा है और अपने समूचे उत्पादन की बिक्री आवेदक को की जा रही है। कंपनी द्वारा उत्पादित टायर कॉड फैब्रिक के बारे में उजरती कार्य ग्राम सहकारी स्वामित्व वाली कंपनी मै. झेंगजियागेंग लियूमिंग वेलफेयर फैक्ट्री से कराया जाता है। कंपनी द्वारा अपने खुद के उत्पाद की बिक्री की जाती है और इस प्रकार से खरीदे गए/उजरती कार्य पर किए गए उत्पादन की बिक्री घरेलू या निर्यात बाजार में की जाती है। अतः आवेदक और राज्य की स्वामित्व/नियंत्रण वाली कंपनियों के बीच अंतर संबंधित कारोबारी प्रचालनों के कारण बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता।
- ङ. आवेदक ने एक ऐसे संयंत्र की खरीद की है जो राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी थी। ऐसा मामला होने के कारण यह अनुरोध किया गया है कि राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी से उक्त कंपनी द्वारा संयंत्र की खरीद की प्रक्रिया प्राधिकारी द्वारा जांच किया जाने वाला सर्वाधिक आधारभूत मापदंड है। निर्यातक के लिए इस बात की पुष्टि करना अपेक्षित है कि परिसंपत्तियों की बिक्री मुक्त रूप से और निजी स्वामित्व को कंपनी के हस्तांतरण के दौरान बाजार कीमत पर की गई थी।
- च. आवेदक संबंधित कंपनियों का जटिल जंजाल है। ऐसा प्रतीत होगा कि ये कंपनियां निजी कंपनियां हैं। यह भी प्रतीत होगा कि ये कंपनियां एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि ये कंपनियां आवेदक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं तथा स्वामित्व एवं नियंत्रण में अंतर संबंध है जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि ये कंपनियां और कुछ नहीं अपितु एक सामूहिक वाणिज्यिक कंपनी हैं।
- छ. आवेदक एक सामूहिक स्वामित्व वाला उपक्रम है। सामूहिक स्वामित्व वाले उपक्रम को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा न देने के मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ था और ऐसा माननीय न्यायाधिकरण ने भी निर्णय लिया था। माननीय न्यायाधिकरण ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय को बरकरार रखा कि सामूहिक स्वामित्व वाले उपक्रम बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के हकदार नहीं हैं।



- ज. कंपनी के कर्मचारियों द्वारा इस कंपनी में भारी निवेश किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी से (क) कर्मचारियों द्वारा निवेशित निधियों के स्रोतों, (ख) जिन निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत कर्मचारियों को ऐसे शेयरों की पेशकश की गई थी, की जांच करने का अनुरोध किया जाता है।
- झ. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के लिए ऐसी भारी क्षमताओं को जोड़ा है, जो न केवल चीन के लिए बल्कि वैश्विक वर्तमान एवं संभावित मांग के अनुपात से काफी भिन्न है और यह कि प्रौद्योगिकी एवं निवेश की लागत के बारे में कंपनी के निर्णय को आपूर्ति एवं मांग को प्रदर्शित करने वाले बाजारी संकेतकों का उत्तर नहीं माना जा सकता है। ये निवेश एनटीसीएफ की न केवल चीनी बाजारों अपितु वैश्विक बाजार में भी वर्तमान और संभावित मांग के अनुपात से पूर्णतः अधिक है। स्पष्ट तौर पर चीनी बाजार अब भारी बेशी सामग्री से पटा हुआ है। इस प्रकार, कंपनी का क्षमता के सृजन में निवेश करने का निर्णय न केवल बाजारी मांग एवं आपूर्ति के प्रत्युत्तर में नहीं है बल्कि इसका तात्पर्य यह भी है कि चीनी बाजार में परिणामी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें एनटीसीएफ की कीमतें असामान्य हों। कंपनी द्वारा किए गए भारी आनुपातिक निवेशों के लिए कंपनी की निधि के स्रोतों की जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विस्तार से की जानी चाहिए। इस बात की जांच अपेक्षित है कि इन निवेशों में राज्य का कोई हस्तक्षेप अथवा उसकी कोई सहायता का प्रावधान नहीं है।
1. चीनी बाजार में एनटीसीएफ की बिक्री कीमतें इन कारणों से राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त नहीं हैं कि (क) चीन में अधिकांश एनटीसीएफ आपूर्तिकर्ताओं का स्वामित्व या नियंत्रण राज्य के पास है, (ख) संयंत्रों के अर्जन की लागत से उचित बाजार मूल्य का पता नहीं चलता है और इन संयंत्रों की पेशकश मुक्त रूप से नहीं की गई है; (ग) निवेश संबंधी निर्णय मौजूदा एवं संभावित मांग तथा आपूर्ति के अनुपात में नहीं है, (घ) चीन के उत्पादकों द्वारा सृजित भारी बेशी क्षमता से आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यंत दबाव पड़ रहा है, (ङ) अधिकांश चीन के उत्पादकों के लिए केप्रोलेक्टम की कीमतों से उचित बाजार मूल्य का पता नहीं चलता है, (च) विद्युत आधारभूत निविष्टियों में से एक है जिसकी कीमतें इन संयंत्रों में राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर उत्पादक दर उत्पादक अलग-अलग हैं, (छ) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन के एनटीसीएफ बाजार में सहायता एवं सब्सिडी की तदर्थ प्रणाली विद्यमान है, एनटीसीएफ उत्पादकों की वित्तीय स्थिति अत्यंत खराब है। इन सभी मापदंडों से अलग-अलग और सामूहिक रूप से ऐसी स्थिति का पता चलता है जिसमें चीनी बाजार में एनटीसीएफ की कीमतें अत्यंत विकृतिकारी और पूर्णतः अविश्वसनीय हैं।
- ट. आवेदक की निर्यात कीमत चीन के निर्यातकों से कम है और पाटन मार्जिन में वस्तुतः वृद्धि हुई है।
- ठ. चीन के बाजार में कंपनी की बिक्री कीमत लगभग 18-21 माह से स्थिर रही थी - जो किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनी के लिए खासकर उस स्थिति में संभव नहीं है जब निविष्टियों की कीमत में उतार-चढ़ाव रहा हो।
- ड. कंपनी की कीमतों में केप्रोलेक्टम की कीमत का उल्लेख तब किया गया है जब उसकी कीमतों में गिरावट आई थी। जब केप्रोलेक्टम की कीमतों में वृद्धि हुई तो कंपनी ने कीमतों में वृद्धि

नहीं की। कंपनी को कैप्रोलेक्टम पर लाभ नहीं मिला तथापि, निर्यात कीमत कम है। कारोबारी निर्णय के परिणामस्वरूप निर्यातक को भारी वित्तीय घाटे की स्थिति का सामना करने के लिए बाध्य होना पड़ा जो उसकी वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है। इससे यह पता चलेगा कि क्या निर्यातक को इतनी कीमतों पर निर्यात जारी रखना चाहिए था।

द. यह अनुरोध किया गया है कि कंपनी द्वारा दावा किए गए समुद्री भाड़े के कारण हुए व्यय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए यदि वह वाहन चीन का वाहन हो।

#### मै. जुना टायर कॉर्ड कं. लि. द्वारा किए गए अनुरोध (न्यू शिपर)

20. यह आरोप लगाया गया है कि न्यू शिपर द्वारा झांगजियागेंग लियुमिंग वेलफेयर फैक्ट्री तथा झांगजियागेंग नायलोन टायर कॉर्ड कंपनी से विचाराधीन उत्पाद की खरीद की जा रही है और ये कंपनियां एक ही परिसर में स्थित हैं। प्रथमतः न्यू शिपर का यह अनुरोध है कि ये न तो उसमें सूचीबद्ध इन कंपनियों में से किसी भी कंपनी में से संबंधित है और न ही ये संबंध वस्तु के उत्पादन और बिक्री में कहीं भी संबंधित हैं। जुनमा बाजार आसूचना के अनुसार झांगजियागेंग नायलोन टायर कॉर्ड कंपनी ने वर्ष 1991 से सरकारी प्राधिकारियों के पास कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना बंद कर दिया है। चीन के कानून के अनुसार सरकारी प्राधिकारियों के पास दस्तावेज प्रस्तुत न करने वाली कोई कंपनी कोई प्रचालन नहीं करेगी और इस प्रकार उसके पास बीजक, प्राप्तियां या कारोबारी प्रचालन हेतु वार्षिक रूप से समीक्षित आवश्यक कारोबार लाइसेंस जारी करने का प्राधिकार या शक्ति नहीं होगी। जहां तक अन्य कंपनी अर्थात् झांगजियागेंग लियुमिंग वेलफेयर फैक्ट्री का संबंध है, यह कंपनी न्यू शिपर के उसी परिसर में स्थित नहीं है। उनके पास अपने खुद की फैक्ट्री और सुविधाएं हैं जो न्यू शिपर की फैक्ट्री से लगभग 2 किलोमीटर दूर है।

21. जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि चीन में अधिकांश टायर कॉर्ड फैब्रिक संयंत्र राज्य के पास हैं और राज्य के स्वामित्व वाले कई संयंत्र अब निजी प्राधिकरणों के पास हैं, यह अनुरोध किया गया है कि मै. जुनमा टायर कॉर्ड कंपनी (पूर्व में स्टीड केमिकल फाइबर कं. लि. के रूप में ज्ञात) एक संयुक्त स्टॉक लिमिटेड कंपनी है जो चीन के जियांगसु प्रांत में अवस्थित है। इस कंपनी को एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में 12 जून, 1998 को चीन में निगमित किया गया था। इस कंपनी को 19 जुलाई, 2000 को एक संयुक्त स्टॉक कंपनी में परिवर्तित किया गया था। यह कंपनी 25 नवंबर, 2004 को सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध की गई थी। न्यू शिपर एक स्वतंत्र स्वामित्व वाली और प्रबंधित कंपनी है और इसे 28 सितंबर, 2002 को आईएसओ 9001 प्रमाणन भी प्रदान किया गया है जो ठोस प्रलेखन नियंत्रण, बेहतर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों और बेहतर विनिर्माण पद्धतियों को अपनाने वाली कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से औद्योगिक मान्यता है।

22. संबंधित कंपनियों के मुद्दे के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि न्यू शिपर ने संगत स्थानों पर निर्यातक प्रश्नावली तथा एनएमई प्रश्नावली में समस्त संबंधित पार्टियों की सूचना उपलब्ध कराई है और इसका वार्षिक रिपोर्टों में समर्थन किया है तथा लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। वस्तुतः उक्त जांच में अत्यधिक पारदर्शिता बरती गई है और एनएमई प्रश्नावली में कच्ची सामग्री सीपीएल के माहवार आपूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं।

23. जहां तक आवेदक और राज्य की स्वामित्व/नियंत्रण वाली कंपनियों के बीच अंतर संबंधित कारोबारी प्रचालनों का संबंध है, यह अनुरोध किया गया है कि विद्युत संयंत्र की खरीद के बारे में विद्युत की आपूर्ति किसी कंपनी को सीधे नहीं की जाती है। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर संभावना सूची में उल्लिखित लेखा परीक्षित दस्तावेजों में संबंधित पार्टी के सौदों की जांच की गई है और सूचना दी गई है जिसमें किसी भी विद्युत कंपनी को न्यू शिपर से संबंधित नहीं बताया गया है। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों की कड़ी जांच और केपीएमजी जैसी अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा फर्म की भागीदारी में भी किसी लियुमिंग वेलफेयर फैक्ट्री, झांगजियागेंग युगसिंग पोलिस्टर प्रोडक्ट्स कं. लि. के नाम का भी पता नहीं चला है। उपर्युक्त विद्युत संयंत्रों को जुनमा से संबंधित कंपनी होने का भी पता नहीं चला है जिससे स्पष्टतः यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए आरोप अप्रमाणित और अवांछित हैं।

24. जुनमा के उत्पादों की कीमत और मात्रा का निर्धारण पूर्णतः जुनमा द्वारा किया जाता है और इसके कारोबारी भागीदार उक्त अवधि के दौरान प्रचलित बाजारी कीमतों और संबद्ध वस्तु के लिए कच्ची सामग्री और प्रयुक्त अन्य निविष्टियों की खरीद पर पूर्णतः आधारित होते हैं। इसके अलावा, जुनमा के संबंध में किसी व्यापार या उत्पादन की कीमत तय करने या उसकी मात्रा का निर्धारण करने में किसी स्थानीय या क्षेत्रीय प्राधिकरण या राज्य को शामिल नहीं किया गया है।

25. जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि जुनमा टायर कोर्ड जो राज्य के स्वामित्व वाला एक संयंत्र था, अब निजी कंपनियों के हाथ में है, यह अनुरोध किया गया है कि कंपनी के सृजन के बारे में सूचना निर्यातक प्रश्नावली और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के समय कंपनी की संभावना सूची तथा वार्षिक रिपोर्ट जैसे सार्वजनिक दस्तावेजों में भी प्रदान की गई है। यह भी अनुरोध किया गया है कि इस विस्तार में कोई राज्य उद्यम या सामूहिक स्वामित्व वाली कंपनी शामिल नहीं है। लेखा परीक्षित वित्तीय रिपोर्ट में प्रकटित विस्तार हेतु उधार में निधियों के स्रोत के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

26. जहां तक उस कीमत, जिस पर संयंत्र की बिक्री की गई थी, और उसके औचित्य का संबंध है, यह अनुरोध किया गया है कि संयंत्र में जिस कीमत पर निवेश किए गए हैं, उसका सत्यापन उसे प्रमाणित करने वाले लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र से किया जा सकता है। जहां तक औचित्य का संबंध है, जिन आंतरिक दस्तावेजों के आधार पर ये निवेश किए गए थे, उनसे केवल तर्कसम्मत तथा वाणिज्यिक आधार की पूर्ति होगी क्योंकि ये निवेश वस्तुओं की बिक्री नहीं हैं जिन्हें दैनिक आधार पर किया जाता है और यह कि सौदा मूल्य को उसी अवधि के दौरान बाजार में की गई समनुरूप बिक्री के आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

27. जहां तक कर्मचारियों द्वारा किए गए निवेश के मुद्दे का संबंध है, यह अनुरोध किया गया है कि समस्त 50 शेयर धारक न्यू शिपर के लिए कार्यरत चीन के अलग-अलग व्यक्ति थे और निवेश कंपनी की स्थापना मूलतः केवल कर्मचारियों के लिए कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व स्कीम को सुकर बनाने के लिए की गई थी।

28. जहां तक मांग में आनुपातिक वृद्धि के बिना अतिरिक्त क्षमता के मुद्दे का संबंध है, यह अनुरोध किया गया है कि न्यू शिपर द्वारा घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की पर्याप्त मात्रा की बिक्री की जा रही है और इस प्रकार वे बाजारी मांग के अनुसार निविष्टि और बिक्री के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं, जिसकी पुष्टि कंपनी के रिकार्डों से की जा सकती है। यह भी अनुरोध

किया गया है कि इस मुद्दे पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध चीन की मांग और वैश्विक मांग के संबंध में स्पष्टतः किसी वास्तविक साक्ष्य से रहित हैं और इस प्रकार क्षमता वृद्धि के मुद्दे पर अनुपात से हटकर जोर दिया जा रहा है जो आधारहीन चिंता या भय से मुक्त हैं जिसके तहत घरेलू उद्योग द्वारा प्रतिस्पर्धी तथा उचित व्यापार की दृष्टि से न्यू शिपर को अनुमति देने से वंचित किया जा रहा है ।

29. जहां तक विस्तार हेतु प्रयुक्त निधियों के स्रोत के मुद्दे की जांच का प्रश्न है, यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा कंपनी के प्रचालनों के खिलाफ अत्यंत भेदभाव का दुर्लभ मामला बनाया जा रहा है क्योंकि कंपनी, जो चीन में संबद्ध वस्तु का एक सबसे बड़ा उत्पादक है और साथ ही साथ जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है और जवाबदेह भी है, जिसके आधार पर स्टॉक एक्सचेंज तथा उसकी खुद की सरकार द्वारा भी कंपनी पर कड़े विनियम लागू किए जाते हैं, के प्रचालनों के बारे में संदेह किया गया है ।

30. जहां तक राज्य के पर्याप्त हस्तक्षेप और संयंत्र, प्रौद्योगिकी, श्रम, निवेश और उत्पाद की आपूर्ति के कारण बिक्री कीमत तथा उत्पादन लागत कृत्रिम रूप से कम होने के मुद्दे का संबंध है, अनुरोध है कि राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है जैसा कि अनुरोधों में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है ।

31. कंपनी द्वारा भारी घाटा उठाए जाने के मुद्दे के बारे में यह अनुरोध है कि इसे पाटन के आरोपों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि ऐसे कुछेक कारोबारी निर्णय और कारोबारी जोखिम हो सकते हैं जिनकी वजह से कंपनी को उक्त अवधि के दौरान घाटा हो सकता है और यह कि इसकी योजना बनाने के लिए किसी प्रबंधन या उसकी कंपनी की कोई मंशा नहीं हो सकती है ।

32. जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि चीन के बाजार में बिक्री कीमत 18-21 माह तक स्थिर बनी रही और कैप्रोलेम्टम की कीमत में वृद्धि के बाद भी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में सूचना प्रस्तुत कर दी गई है ।

33. समुद्री भाड़े के मुद्दे के संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि जब तक कोई संबंधित पार्टी नहीं है जैसा कि कंपनी के भाड़े के संबंध में इस मामले में घटित नहीं हुआ है, निर्दिष्ट प्राधिकारी को इसके लिए व्यय को सामान्य मामले में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

34. सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (2) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस अनुमान पर कार्रवाई शुरू की है कि ऐसा कोई देश जिसे जांच से पूर्ववर्ती 3 वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ कोई गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानने का निर्धारण किया गया है या उसे माना गया है, वह गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है । पिछले तीन वर्षों के दौरान ईयू तथा अमरीका जैसे डब्ल्यू टी ओ जैसे सदस्यों ने चीन जन.गण. को पाटनरोधी जांचों में गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है । इस मामले में चीन जन.गण. की बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में जांच करने का प्रस्ताव था ।

35. प्राधिकारी ने मै. जुनमा टायर कॉर्ड कंपनी लि., चीन जन.गण. (न्यू शिपर) को बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार (एमईटी) संबंधी प्रश्नावली और निर्यातक प्रश्नावली भेजी। उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार के दावे के समर्थन में उत्तर दिया और अपने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का अनुरोध किया। एमईटी व्यवहार के उनके दावे को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक के परिसरों में सत्यापन किया गया था। न्यू शिपर ने इस आधार पर अलग-अलग व्यवहार का दावा किया है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था वाली स्थिति में प्रचालन कर रहे हैं भले ही उनके कारोबारी कार्यकलाप में राज्य के किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या प्रभाव के बिना देश में प्रचलित अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ भी हो।

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यह उपबंध है कि :

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ का समुचित मार्जिन भी शामिल किया जाएगा।"

37. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-8 (यथासंशोधित) में आगे यह उपबंध है कि:

- (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश शब्द का अर्थ है कि कोई देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के कारण सिद्धांतों को लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"
- (2) यह कहना परिकल्पना होगी कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू टी ओ के किसी सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया अथवा माना गया है, एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।
- (3) तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

38. यह नोट किया जाता है कि न्यू शिपर ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) में यथा उल्लिखित सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या

- (क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों, प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना

होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं;

- (ख) ऐसे फर्मों की उत्पादन लागतें तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती, गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है । खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास, अन्य राइट ऑफ, वस्तु विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;
- (घ) विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं;
- (ङ) तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसे अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं । निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं ।"

39. स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण, वाणिज्यिक एवं कारोबारी नीतियों तथा वित्तीय स्थिति आदि के निर्धारण से संबंधित विस्तृत प्रश्नों के बारे में आवेदक को जानकारी दी गई थी । न्यू शिपर द्वारा दायर उत्तरों का विश्लेषण किया गया था ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या आवेदक ने उस स्थिति की तुलना में चीन की सरकार से स्वतंत्र रूप से किस हद तक कार्य किया है जो किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में प्रचलित रही होगी । प्राधिकारी ने आवेदकों से निम्नलिखित मापदंडों के संबंध में सामान्य एवं कुछेक विशिष्ट सूचना मांगी :-

- स्वामित्व संबंधी ब्यौरे
- शेयरधारिता की पद्धति
- प्रवर्तक/नियंत्रक कंपनी/कंपनियों से संबंधित सूचना
- निदेशक मंडल का गठन, उसकी विधिक स्थिति तथा उसमें प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति/पार्टी
- कच्ची सामग्री संबंधी निविष्टि और लागत
- उत्पादन सुविधाएं एवं लागत
- ऋण एवं सब्सिडी
- वस्तु विनिमय व्यापार/प्रति व्यापार
- लाभ का वितरण
- दिवालियापन एवं संपत्ति कानून
- विनिमय दर परिवर्तन

40. इस बात की जांच करने के लिए कि क्या आवेदक के संसाधनों के आबंटन और निर्णयों पर राज्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस हद तक दबाव या हस्तक्षेप था, याचिकाकर्ता के स्वामित्व की पद्धति की जांच की गई थी । हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए दावों/प्रति दावों को ध्यान में रखा गया था और इस संबंध में प्रस्तुत ब्यौरों का सत्यापन किया गया था ।

**कंपनी का स्वामित्व**

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* का नाम बदलकर जियांगसु जुनमा ग्रुप कंपनी लि. रख दिया गया था ।

42. मै. जुनमा नाइलोन को 12.6.1998 को निगमित किया गया था (पंजीकृत पूंजी आरएमबी \*\*\*) जिसमें जुनमा ग्रुप की शेयरधारिता पर संपत्तियों के रूप में 20%, लेबर यूनियन 71.96% श्री चैनज्यूफ्यू 4.44% और श्री ल्यूझेंगफेंग 3.6% थी । बाद में दिनांक 24.7.1999 को जुनमा ग्रुप कंपनी ने जुनमा नाइलोन में अपने समूचे हित (20%) का अंतरण अन्य मौजूदा शेयरधारकों को कर दिया । दिनांक 1.8.1999 को पूंजी संरचना और शेयरधारिता में बदलाव किया गया था । शेयरधारिता इस प्रकार बनी- लेबर यूनियन (54.8%), चैनज्यूफ्यू (8%), ल्यूझेंगफेंग (8.2%), येंगपीकसिंग(20%), जियांगजियानपिंग (4.5%) और ल्यू याओक्सियांग (4.5%) । जुलाई, 2000 में जुनमा नाइलोन को संयुक्त स्टॉक कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया जिसका नाम बदल कर झांगजियांग जुनमा टायर कॉर्ड कंपनी लिमिटेड रख दिया गया था । दिनांक 7.8.2002 को नाम आगे और बदलकर जुनमा टायर कॉर्ड कंपनी लिमिटेड रख दिया गया था । लेबर यूनियन जिसकी शेयरधारिता 54.8% थी, के स्थान पर बुओले का गठन हुआ ।

43. दिनांक 12.12.2003 को कंपनी की पूंजी संरचना में आगे और परिवर्तन किया गया (पंजीकृत पूंजी आरएमबी \*\*\*), जिसकी शेयरधारिता इस प्रकार थी - बुओले (41%), चैन ज्यूफ (6%), ल्यूझेंगफेंग (6.1%), येंगपीकसिंग(15%), जियांग जियानपिंग (3.4%) और ल्यू याओक्सियांग (3.4%) और "एस शेयर" (25.1%)।

**बुओले की भूमिका**

44. लेबर यूनियन में 121 व्यक्ति शामिल थे जो मुख्यतः जुनमा ग्रुप कंपनी के प्रबंधन तथा उत्पादन कर्मचारी थे और जो जुनमा नाइलोन के कर्मचारी बन गए थे । यह भी स्पष्ट किया गया था कि जुनमा नाइलोन में लेबर यूनियन की शेयरधारिता 71.96% थी और उसने \*\*\* आरएमबी का नकद अंशदान किया था । 20% शेयर जुनमा ग्रुप द्वारा धारित किए गए थे और उसने परिसंपत्तियों के रूप में अंशदान किया था । लेबर यूनियन की शेयरधारिता बदलकर 54.8% कर दी गई थी । लेबर यूनियन की शेयरधारिता जो 121 व्यक्तियों द्वारा धारित थी, को अंतरित कर 53 व्यक्तियों ने धारित की थी । बाद में लेबर यूनियन बुओले बन गई और और 53 व्यक्तियों में से 50 द्वारा स्थापित यह एक निवेश कंपनी बन गई । निर्यातक से बुओले की वार्षिक रिपोर्टें उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था । इस संबंध में यह सूचना दी गई थी कि "बुओले द्वारा वार्षिक रिपोर्टें तैयार नहीं की जाती हैं क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी है जो जुनमा के अलग-अलग शेयरधारकों द्वारा सामूहिक रूप से निगमित जुनमा में निवेश कर रही है । बुओले के पंजीकरण दस्तावेज अलग-अलग शेयरधारकों द्वारा निगमित 100% निजी कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं । हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि पूर्ववर्ती "लेबर यूनियन" के रूप में ज्ञात संस्था का नाम बदलकर बुओले रख दिया गया है । जब जुनमा का निगमन किया गया था तो ऐसे कई शेयरधारक थे जो अलग-अलग निवेशक थे । वर्ष 2002 से "लेबर यूनियन" ने संशोधन कर स्वयं का नाम "बुओले" रख दिया । बुओले के सभी शेयरधारक व्यक्ति हैं जिन पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है ।"

45. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्ष 2004 और 2005 में निर्यातक के बैंक ऋणों पर गारंटी "बुओले" झांगजियागेंग बुओले इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कंपनी लि. (जेडबीआईडीसीएल) द्वारा प्रदान की गई थी ।

### **वरिष्ठ प्रबंधन**

46. वरिष्ठ प्रबंधन के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यांगपिकसिंग, कार्यकारी अध्यक्ष, ल्यूयाओक्सियांग, कार्यकारी निदेशक, ल्यूझोंगफेंग, कार्यकारी निदेशक, झाओझाऊझिडान, कार्यकारी निदेशक, चेनजुफू, गैर कार्यकारी निदेशक और जियांगयूडा, गैर कार्यकारी निदेशक अर्थात् कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन शुरुआत से ही कंपनी के साथ सहयोजित रहा । अर्थात् वे जुनमा ग्रुप में और जुनमा ग्रुप के गठन से पूर्व वरिष्ठ प्रबंधन में शामिल थे ।

### **जुनमा ग्रुप**

47. यह भी नोट किया गया है कि पर्यवेक्षी समिति के श्री यांग रेनमिंग और श्री अक्षु फेंगे जुनमा ग्रुप के कर्मचारी हैं ।

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि "बुओले" जिसे पूर्व में लेबर यूनियन के रूप में जाना जाता था, कंपनी की स्थापना के समय पूंजी के 72% भाग को उपलब्ध कराया और उसने बाद में पूंजी उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी जारी रखी । कंपनी के ऋण पर गारंटी भी "बुओले" {झांगजियागेंग बुओले इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कंपनी लि.} (जेडबीआईडीसीएल) द्वारा प्रदान की गई है । यद्यपि यह स्पष्ट किया गया है कि बुओले केवल निवेश कंपनी है और वह केवल जुनमा में निवेश कर रही है परंतु बुओले जो कि पूर्व में लेबर यूनियन के रूप में ज्ञात थी, की निधियों के स्रोत के बारे में कोई सूचना और साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है । इस बात का उल्लेख करने वाले किसी पारदर्शी और विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में कि दावा किए गए अनुसार निवेश व्यष्टियों द्वारा किए गए हैं, प्राधिकारी इस दावे को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं कि यह एक व्यष्टियों की निवेश कंपनी है जिसने पूंजी उपलब्ध कराई है । यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसी परिसंपत्ति के बिना बुओले द्वारा किस प्रकार जुनमा टायर कॉड कंपनी लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋणों के लिए बैंकों को गारंटी प्रदान की जा सकती है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन उससे सहयोजित रहा है और उसमें राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी से निजी कंपनी के रूप में रूपांतरण के दावे के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट से नोट किया गया है, दो अधिकारी जो जुनमा ग्रुप के कर्मचारी हैं, वे कंपनी की पर्यवेक्षी समिति में हैं, न्यू शिपर का यह दावा कि कंपनी राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी से रूपांतरित होकर निजी कंपनी बन गई है, जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता । ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी रूपांतरण के चरण में है । अपारदर्शी ढंग से बुओले (पूर्ववर्ती लेबर यूनियन) द्वारा निवेश और ऋण की गारंटी, निजी कंपनी में रूपांतरण के दावे के बाद भी वरिष्ठ प्रबंधन के बने रहने से यह संकेत मिलता है कि न्यू शिपर द्वारा अब भी गैर बाजारी स्थितियों में कार्य किया जा रहा है क्योंकि कंपनी के निवेश एवं कीमतों के बारे में निर्णयों से संबंधित राज्य के पर्याप्त हस्तक्षेप से इंकार नहीं किया जा सकता है । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि न्यू शिपर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा 8(3) के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन करने में विफल रहा है ।

### **ड. पाटन मार्जिन की गणना हेतु कार्य प्रणाली**

#### **ड.1 सामान्य मूल्य**

49. न्यू शिपर ने जांच अवधि के दौरान की गई घरेलू बिक्रियों के सौदेवार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं । निर्यात बिक्री से तुलनीय घरेलू बिक्री के स्वरूप का पता लगाने के लिए कंपनी से उसके द्वारा प्रयुक्त कोडिंग प्रणाली के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था । यह स्पष्ट किया गया



था कि कोडिंग प्रणाली का संदर्भ फैब्रिक के प्रकार, डेनियर तथा बिक्री (घरेलू एवं निर्यात) के स्वरूप से है। यह नोट किया गया था कि घरेलू बिक्री के बीजकों में 100 से अधिक कोडों का उपयोग किया गया है। निर्यातक से अलग-अलग कोडों के अर्थ और उनके वर्गीकरण को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है और इस प्रकार निर्यात बिक्री की तुलना में घरेलू बिक्री में उत्पाद के प्रकार को सुनिश्चित करना संभव नहीं है। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यू शिपर गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन करने में विफल रहा है, सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया जा सकता। अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण उक्त अनुबंध के पैरा 7 के अनुसार "किसी अन्य यथोचित आधार पर" किया गया है।

50. सामान्य मूल्य का परिकलन जांच अवधि के दौरान प्रयुक्त कार्य प्रणाली को अपनाकर किया गया है। परिकलन हेतु चीन जन.गण. के लिए औसत आईसीआईएस एलओआर कीमतों के आधार पर जांच अवधि के दौरान प्रचलित कैप्रोलेक्टम की कीमत को अपनाया गया है। यह देखा गया है कि न्यू शिपर की कैप्रोलेक्टम खरीद कीमत (जिसमें वेट और पाटनरोधी शुल्क, जहां लागू हो, शामिल हैं) को अपनाकर अंतिम कीमत घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे से अधिक बनती है। मूल जांच के समय अपनाई गई परिवर्तन लागत को 5% के लाभ मार्जिन की अनुमति देते हुए अपनाया गया है। तदनुसार ग्रे के परिकलित सामान्य मूल्य (सीएनवी) को घरेलू उद्योग के दावे तक सीमित रखा गया है। डिण्ड फैब्रिक के मामले में वर्तमान कीमत की तुलना में मूल जांच के समय प्रचलित कीमत के आधार पर तुलनात्मक कीमत वृद्धि की अनुमति दी गई है।

51. ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को एनटीसीएफ के दो प्रकारों (डिण्ड और ग्रीज) का निर्यात किया है। ऊपर स्पष्ट की गई कार्य प्रणाली के आधार पर एनटीसीएफ के इन प्रकारों के लिए प्रकारवार सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

| क्र.सं. | विवरण          | सामान्य मूल्य (अम.डॉ. प्रति किग्रा.) |
|---------|----------------|--------------------------------------|
| 1.      | एनटीसीएफ डिण्ड | ***                                  |
| 2.      | एनटीसीएफ ग्रीज | ***                                  |

## ड.2 निर्यात कीमत

52. प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों के बीजकवार/प्रकारवार ब्यौरे परिशिष्ट -2 में प्रस्तुत किए हैं। निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन मूल रिकार्डों से किया गया है। भारत को निर्यात सीआईएफ आधार पर किए गए हैं। निर्यातक ने अंतरदेशीय भाड़े, अंतर्राष्ट्रीय भाड़े, अंतर्राष्ट्रीय बीमा, कमीशन हेतु व्यय के लिए समायोजनों का दावा किया है। समायोजनों के बारे में सत्यापित आंकड़ों को हिसाब में लेने के बाद कारखाना निर्यात कीमत की गणना की गई है। संबद्ध वस्तु की प्रकारवार कारखाना निर्यात कीमत निम्नानुसार बनती है :-

| क्र.सं. | विवरण          | निर्यात कीमत (अम.डॉ. प्रति किग्रा.) |
|---------|----------------|-------------------------------------|
| 1.      | एनटीसीएफ डिण्ड | ***                                 |
| 2.      | एनटीसीएफ ग्रीज | ***                                 |

### 4.3 पाटन मार्जिन

53. अलग-अलग प्रकारों के लिए ऊपर उल्लिखित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के बाद नायलोन टायर और फैब्रिक (एनटीसीएफ) हेतु भारित पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। यह पाया गया है कि निर्यातक ने संबद्ध वस्तु का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया है और भारित औसत पाटन मार्जिन \*\*\* अम.डॉ./किग्रा. निर्धारित किया गया है।

### च. प्राधिकारी की सिफारिशें

54. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि

- i) मै. जुनमा टायर कॉर्ड कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. द्वारा उत्पादित और भारत को निर्यातित नायलोन टायर कॉर्ड फैब्रिक (एनटीसीएफ) की निर्यात कीमत जांच अवधि के दौरान उसके सामान्य मूल्य से कम रही है।
- ii) अतः प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि मै. जुनमा टायर कॉर्ड कं. लि., चीन जन.गण. द्वारा उत्पादित और भारत को निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 59 के अंतर्गत आने वाले नायलोन टायर कॉर्ड फैब्रिक (एनटीसीएफ) के आयातों पर 51.36 भारतीय रूपए प्रति किग्रा.का पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

55. इस आदेश के खिलाफ कोई अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2008

### Final Findings

(New Shipper Review)

**Subject : New Shipper Review (under rule 22 of AD Rules) of anti-dumping duty imposed on imports on Nylon Tyre Cord Fabrics (NTCF) requested by M/s Junma Tyre Cord Co. Ltd., China PR.**

**No. 15/11/2006-DGAD.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

### A. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed:

- (i) The Designated Authority received a request from M/s Junma Tyre Cord Co. Ltd., China PR (hereinafter referred to as New shipper) to initiate under Rule 22 of above mentioned Rules a review of notification

No.14/20/2003-DGAD dated 9.3.2005 for determination of individual dumping margin. The applicant submitted declarations that they are not related to any of the exporters and producers in China PR subject to the anti dumping measures in force with regard to the product concerned. Furthermore, they declared that they have not exported the product concerned during the period of investigation of the original investigation. The Authority examined the information submitted by the applicants and considered prima-facie sufficient to justify the initiation of a review in accordance with the provisions of the Rule 22 of Anti-dumping Rules.

- (ii) The Authority initiated the New Shipper Review on the basis of request made by /s Junma Tyre Cord Co. Ltd., China PR (producer and exporter) under Rule 22 of AD Rules, vide notification No. 15/11/2006-DGAD, dated 11.7.2006.
- (iii) The aforesaid New Shipper Review was initiated in the matter of import of Nylon Tyre Cord Fabrics (NTCF) falling under Chapter 59 of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from China PR where the Designated Authority vide its Final Findings No.14/20/2003-DGAD dated 9.3.2005 had come to the conclusion that:
  - (a) NTCF of all types, originating in or exported from the subject country has been exported to India below normal value, resulting in dumping;
  - (b) The domestic industry has suffered material injury;
  - (c) Material injury has been caused by dumped imports from the subject country.
- (iv) The Central Government imposed anti-dumping duty vide Notification No. 36/2005-Customs dated 27.4.2005, in the original investigation on imports of Nylon Tyre Cord Fabrics (NTCF) from China PR falling under Chapter 59 of Customs Tariff Act;
- (v) The Authority recommended provisional assessment of all exports of Nylon Tyre Cord Fabrics (NTCF) made by M/s. Junma Tyre Cord Co. Limited, China P.R. (producer and exporter) till the completion of the New Shipper review in accordance with Rule 22 of AD Rules and having regard to the Notification no.36/2005-Cus dated 27/4/2005;
- (vi) Ministry of Finance issued Notification No. 84/2006-Customs, dated 29<sup>th</sup> August, 2006, which inter-alia provided that pending the outcome of the review by the Designated Authority, exports of Nylon Tyre Cord Fabrics (NTCF), falling under Sub-heading 590210 of the first scheduled of the said Customs Tariff Act. by M/s. Junma Tyre Cord Co. Limited, People's Republic of China, when imported into India would be subjected to provisional assessment till the review was completed. It was further provided that the provisional assessment may be subject to security or guarantee as the proper officer of the Customs deems fit for payment of the deficiency, if any, in case a definitive anti dumping duty is imposed retrospectively, on completion of the investigation by the Designated Authority. In case of recommendation of Anti-Dumping Duty after completion of the said review by the Designated Authority, the importer shall be liable to pay the amount of such duty recommended on review and imposed on all imports of subject goods into India,

exported by M/s Junma Tyre Cord Co. Limited, People's Republic of China, and imported into India, from the date of initiation of the said review.

- (vii) The Authority sent a copy of exporter's questionnaire and Market Economy Treatment (MET) questionnaire to M/s. Junma Tyre Cord Co. Limited, China P.R. (producer and exporter). The Authority sought information it deemed necessary for the purpose of determination of dumping margin. The Authority conducted verification of the data furnished by M/s. Junma Tyre Cord Co. Limited, (producer and exporter) at their premises.
- (viii) The period of investigation in this new shipper investigation is for 12 months i.e., 1<sup>st</sup> April, 2005 to 31<sup>st</sup> March, 2006 for dumping determination.
- (ix) The Authority officially intimated the authority of the exporting country of the initiation of the New Shipper Review and gave opportunity to all the interested parties concerned to make their views known in writing within 40 days from the date of issue of notification i.e. 11.7.2006.
- (x) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in the public hearing held on 30.11.2006. All parties presenting their views orally were requested to file written submissions of the views expressed verbally.
- (xi) The Authority made available the public file as per Rule 6(7) to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request.
- (xii) In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received thereon have also been duly considered in the findings.
- (xiii) \*\*\* in the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the Rules. The information concerning prices and costing filed by the applicant were claimed confidential and these were treated as confidential by the Authority;

#### **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. This being a Review for determination of individual dumping margin under Rule 22 of the Rules, therefore, the product under consideration as described in the original investigation No.14/20/2003-DGAD dated 8.3.2005 will remain same. No issue in this regard has been raised by any of the interested parties. In the original investigation, the product under consideration has been described in para 3 of the findings as under:-

*"The product under consideration in the present case is Nylone Tyre cord Fabric (NTCF) originating in or exported from Peoples Republic of China. The subject good is a fabric of nylone, meant largely for tyre cord. NTCF finds application in different kinds of automotive tyres such as bus & truck tyres, two wheeler tyres, cycle tyres, light commercial vehicles tyres, animal driven vehicles, etc.*

*Nylone Tyre Cord Fabric is produced using different deniers of yarn. The fabric is used for reinforcement of tyres. The product is sold as "Grey fabric" and also "Dipped fabric". The Indian tyre industry is buying both Grey and dipped fabric. Dipped fabric being sold to cycle tyre manufacturers is described by the petitioner as "cycle tyre fabric". However, the authority notes that cycle tyre fabric is also nothing but dipped fabric, though having higher cost and price as compared to other dipped fabric being sold to tyre producers other than cycle tyre manufacturers. Dipped fabric meant for cycle tyre applications has been described as cycle tyre fabric (CTC) in this notification and all other dipped fabric has been stated as "dipped fabric". Irrespective of the categorisation, tariff classification of NTCF is common to both. All types of NTCF are within the scope of the product under consideration and are classified under Chapter 59, Custom sub-heading No.5902.10.00 of the Customs Tariff Act. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation."*

4. The new shipper has stated that they have exported NTCF of types Greige and Dipped. From the records it was noted that the new shipper has exported mainly NTCF greige i.e. 91% and NTCF dipped was only balance 9%.

### **C. Other Issues**

#### **C.1 Issue of Normal Value**

5. The Indian exporters on behalf of M/s. SRF Ltd., M/s Century Enka Ltd., and M/s NRC Ltd. have stated that the investigation cannot proceed in the present form and manner in view of the decision of Supreme court in matter of M/s Reliance Industries Ltd. Vs. The Designated Authority [(2006(202)ELT 23 (SC)] as the Supreme Court has held that normal value is country-specific and clearly lays down that normal value shall not be for the exporter.

6. The New Shipper in this regard has pointed out that as per Annexure 1 of the Anti-dumping Rules, the normal value is to be determined on the basis of the records kept by the exporter or producer under investigation. In this investigation, the new shipper is the exporter under investigation. It has also been submitted that jurisprudence on interpretation of statutes clearly state that the intention of legislature is primarily to be gathered from the language used; thus stating that unless otherwise warranted, the plain language of the statute must be given effect to.

7. The Authority has examined the issue and notes that the CESTAT in Order dated 27.8.2007 in appeal No.01 of 2007 in case of M/s H & R Johnson (India) Ltd. Vs. Ministry of Finance and Designated Authority has observed that the observation of Supreme court concerning normal value "*are not intended to apply to the scheme of provisions of rule 22 under which the individual dumping margin of the new shipper is required to be determined*". In view of the observation of the CESTAT, the Authority holds that the argument of the domestic industry concerning normal value in context of new shipper review under Rule 22 is not valid.

#### **C.2 Qualification of Junma as a New Shipper**

8. Submissions made by Indian producers on behalf of M/s. SRF Ltd., M/s Century Enka Ltd., and M/s NRC Ltd.
9. It has been submitted that Junma does not qualify as a new shipper as the company has provided no evidence that company qualifies as a new shipper. All that

the petition shows in this regard is mere claim on behalf of the company. However, no supporting evidence has been presented by the applicant in this regard.

10. Even considering the practice of the Designated Authority, it is evident that present application did not meet the requirements being considered necessary by the Designated Authority. The company has filed only authorisation letter, business licence of the company, audited financial statement for 2005, company's brochure and declaration of 'no exports' in the period of investigation in the original investigation. This information cannot constitute evidence to establish that they did not export during the previous dumping investigation period. It has also been stated that information on production facilities has been suppressed in the application.

11. It has been stated that Indian producers understand that Junma had exported the subject goods to India either during or prior to the investigation period. Junma, however, provided no details of these exports either at the time of original investigation or in the current application. Thus, while the company was non-cooperating in the previous investigations, the company has filed insufficient/incomplete information in the present application.

12. It has also been stated that unless all entities who have been involved in the production or sale or activity connected therewith respond to the Designated Authority, the investigation cannot be continued.

#### **Submissions made by New Shipper**

13. It has been submitted that the new shipper has filed the certificate of incorporation having the date of commencement of business. The intention of initiation of new shipper which has been recorded by the Authority and the change in the name of the company. The exports of the subject goods were clearly outside the period of investigation fixed in the original investigation. The applicant in their response to the questionnaire also have certified that they had no affiliated/related company engaged in production or sale of the product concerned who were subjected to anti-dumping duties either. It has also been submitted that new shipper has clearly responded to all the queries/clarification of the Authority prior to initiating the investigation. The Authority has looked into these issues and has rightly initiating the investigation within the framework of the applicable rules and the practice followed by the Authority from time to time.

14. On issue of separate questionnaires responses from each related entity, it has been submitted that there is no related party involved in the production or sale of the subject goods or any companies involved who have a job work arrangement, therefore, the question of filing separate questionnaires does not arise.

#### **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

15. The Designated Authority initiated new shipper review keeping in view the provisions of the anti dumping rules, which are reproduced below:

- (a) "Rule 22: (1) *If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose*

- of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti dumping duties on the product.*
- (b) *The Central Government shall not levy anti dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act, on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:*
  - (c) *Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of initiation of the review”.*

16. Rule 22 clearly specifies the circumstances under which a new shipper investigation can be carried out for the purpose of calculating individual dumping margin. Individual dumping margin in respect of any exporter or producer from the exporting country in question can be determined provided the following two conditions are satisfied;

- (a) that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation and,
- (b) that exporter or producer shows that they are not related to any of the exporter or producer in the exporting country who are subject to the anti dumping duties on the product concerned.

17. The Designated Authority in the present case on the basis of information filed by the applicant found that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation in the original investigation and provided certification that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to anti dumping duties. The Authority before initiating the investigation called documents like Article of Association and Annual Reports, etc. which could have revealed the relationship of the applicant with the other entities and exports made by them so that the veracity of the declaration could be checked. At the time of initiation the Authority did not find any information/evidence indicating that declarations filed by the applicant were false. In absence of any credible information no adverse inference could be drawn against the applicant.

18. During the investigation the Authority neither found any evidence of relationship with any of the exporters and producers in China PR who are subjected to anti-dumping duty nor any material evidence in this regard was brought before the Authority by any interested parties. The Authority, therefore, holds that the New Shipper Review investigation was initiated and conducted as per provisions laid down in Rule 22 of the anti-dumping rules which is in conformity with article 9.5 of the WTO AD Agreement.

#### **D. Issues on Non-Market Economy**

19. Submissions made by Indian producers on behalf of M/s. SRF Ltd., M/s Century Enka Ltd., and M/s NRC Ltd.

- a. All companies engaged in production whose product has been exported to India are not before the Designated Authority.
- b. All plants for production of NTCF were owned or controlled by the Govt. of China. These State owned/controlled plants have been acquired by private entities – in some cases completely in others partially. Such being the case, it is required to be established by the applicant that the ownership of such plant has been transferred to private parties on market price and is not influenced with the erstwhile non-market economy system.
- c. The applicant has a related company supplying power to the company, yet, the reply of the exporter does not seem to have disclosed this. Further, the applicant is buying the product under consideration as also inputs from other related companies, details of which are not disclosed to the Designated Authority.
- d. Indian producers submit that State-owned entity Zhangjiagang Nylon Tyre Cord Factory is still producing tyre cord fabric and selling its entire production to the applicant. The company is setting tyre cord fabric produced on job work basis from Village Cooperative owned company M/s Zhangjiagang Luming Welfare Factory. The company is selling its own product as also such purchased/job work production in the domestic or export market. Therefore, market economy status cannot be granted due to intermingled business operations between the applicant and State-owned/controlled entities.
- e. The applicant has purchased a plant which was with State owned entity. Such being the case, it has been submitted that the process of purchase of the plant by the company from the State owned entity is one of the most fundamental parameter to be examined by the Authority. The exporter is required to establish that the assets were sold freely and at a market price during the transfer of the company to the private ownership.
- f. The applicant is a complex web of related entities. It would appear that these entities are private entities. It would also appear that these entities are unrelated to each other. In this regard it has been stated that the companies are directly or indirectly related to the applicant and the ownership and control is intermingled thus leading to a situation where these entities are nothing but one collective commercial entity.
- g. The applicant is a collectively owned enterprise. The issue of collectively owned enterprise not being entitled to market economy status was debated at length and decided by the Hon'ble Tribunal also. The Hon'ble Tribunal has upheld the decision of the Designated Authority that collectively owned enterprises are not entitled for market economy status.
- h. Huge investments in the company have been made by employees of the company. The Designated Authority is requested to examine (a) sources of the funds invested by the employees, (b) terms and conditions under which such shares were offered to employees.
- i. The applicant has added such massive capacities for the product under consideration, far too disproportionate to not only Chinese but also global present and potential demand that the decision of the company regarding cost of technology and investment cannot be said to be in response to market signals reflecting supply and demand. These investments wholly disproportionate to the present and potential demand of NTCF not only in Chinese market but also in the global market. Evidently, the Chinese market is now saddled with huge surplus material. Thus, not only that the decision of the company to invest in capacity creation is not in response to market demand and supply, but also that the resultant situation in the Chinese market should be one where the NTCF prices are abnormal. The source of



fund of the company for the huge disproportionate investments undertaken by the company should be investigated by the Designated Authority in detail. It is required to be established that there is no state interference or support in these investments.

- j. The selling price of NTCF in the Chinese market is not free from State interference for the reasons that (a) the majority NTCF suppliers in China were owned or controlled by the State, (b) cost of acquiring the plants are not reflective of fair market values and these plants have not been offered freely, (c) investment decisions are disproportionate to the existing and potential demand and supply, (d) huge surplus created by the Chinese producers is leading to extreme pressure on the suppliers, (e) caprolactam prices for the majority Chinese producers is not reflective of fair market values, (f) power is one of the basis inputs, prices of which significantly vary from producer to producer depending upon State ownership or control in these plants, (g) Designated Authority has established that an ad-hoc system of support and subsidies exist in the Chinese NTCF market, (h) financial situations of the NTCF producers are highly distorted. All these parameters individually and collectively have led to a situation where NTCF prices in the Chinese market are highly distortive and wholly unreliable.
- k. The export price of applicant is lower than other Chinese exporters and dumping margin in fact has increased.
- l. Selling price of the company in Chinese market was constant for almost 18-21 months – not possible for a market economy company that too when the inputs are volatile.
- m. The company's prices responded to Caprolactam prices only when the prices of the later declined. When prices of Caprolactam increased, the company did not increase the prices. The company does not have advantage on Caprolactam, yet, export price is so low. As a result of its business decision, the exporter is forced to a situation of huge financial losses, which is evident from its Annual Report. This will only mount, should the exporter continue to export at these prices.
- n. It has been submitted that the expenses on account of ocean freight claimed by the company should not be considered in case the carrier is a Chinese carrier.

#### **Submissions made by M/s Junma Tyre Cord Co. Ltd. (New Shipper)**

20. It has been alleged that the new shipper is buying the product under consideration from Zhangjiagang Luming Welfare Factory and Zhangjiagang Nylon Tyre Cord Co. And they are located in the same premises. Firstly, the new shipper submits that they are not related to any of these companies listed herein nor were concerned in the production or sale of the subject goods. As per Junma's market intelligence, Zhangjiagang Nylon Tyre Cord Co. have ceased to file any documents with government authorities since 1991. According to China law, any company not filing with government authorities shall not carry any operation, thus will not have the authority or the power to issue invoices, receipts or annually reviewed business license necessary for business operation. As regards the other company i.e. Zhangjiagang Luming Welfare Factory, this company is not located in the same premise of the new shipper. They have their own factory and facilities which is around two kilometres away from the factory of the new shipper.

21. Regarding issue of majority of tyre cord fabric plants in China were with the State and number of state owned plants are now with private authorities, it has been submitted that M/s Junma Tyre Cord Co. Ltd. (formerly known as Steed Chemical

Fibre Co. Ltd.) is a joint stock limited company based in the Jiangsu province of China. The company was incorporated in China on 12<sup>th</sup> June, 1998 as a limited liability company. The company was converted into a joint stock company on 19<sup>th</sup> July, 2000. The company was listed on 25<sup>th</sup> November 2004 at the Singapore Stock Exchange. The new shipper is an independently owned and managed company and has also been awarded the ISO 9001 certification, an internationally recognised industry accreditation for companies with sound documentation control, good quality management systems and adherence to good manufacturing practices on 28<sup>th</sup> September, 2002.

22. On issue of related entities, it has been stated that the new shipper at relevant places has provided all the related parties information in the Exporter's questionnaire and the NME questionnaire and to support the same annual reports and auditor's certificates have also been furnished. In fact, the highest levels of transparency been followed in the said investigation to the extent of furnishing month-wise supplier details of the raw material CPL has been provided in the NME questionnaire.

23. On issue of intermingled business operations between the applicant and state-owned/controlled entities, it has been submitted that on purchase of the power plant does not supply directly any power to the company. The audited documents as disclosed in the prospectus filed with the Singapore Stock Exchange has examined and reported the related party transactions, none of the power companies have been shown to be related to the new shipper. The stringent examination of listed companies by the Singapore Stock Exchange and the involvement of an international auditing firm such as KPMG have also not named any Luming Welfare Factory, Zhangjiagang Yuxing Polyester Products Co. Ltd. Or the above power plants as related company of Junma, which is a clear indication that the allegations made by the domestic industry is unsubstantiated and uncalled for.

24. The prices and quantities of Junma's products are solely determined by Junma and its business partners solely based on the market rates prevalent during that period as also with the purchases of the raw materials and other inputs used for the subject goods. Also, no local or regional authority or state has been involved in setting prices or deciding the quantities of any trade or production in relation to Junma.

25. Concerning issue that Junma Tyre Cord was a state owned plant now in the hands of private entities, it has been submitted that the information as to the creation of the company has been disclosed in the exporter's questionnaire and also in the public documents such as prospects of the company at the time of listing on the Singapore Stock Exchange and the Annual Report. It has also been submitted that there is no State enterprise or collectively owned company involved in this expansion. The borrowings for the expansions as disclosed in the audited financial report clearly explain the source of funds.

26. Concerning issue of the price at which the plant was sold and justification thereof, it has been submitted that prices at which investments have been made on the plant can be verified from the auditor's certificate certifying the same. As regards the justification is concerned, the internal documents on the basis of which these investments were made would serve the only logical and commercial basis, as these investments are not commodity sales which are made on a daily basis that the transaction value can be justified on the basis of identical sales made in the market during the same period.

27. Concerning issue of investment by employees, it has been submitted that all 50 shareholders were individual Chinese persons working for the new shipper and the investment company was originally set up only to facilitate the Employee Stock Ownership Scheme for the employees.

28. On issue of additional capacity without proportionate increase in the demand, it has been submitted that the new shipper has been selling substantial quantities of the subject goods in the domestic market and thus freely decides the output and the sales depending upon the market demand as can be ascertained from the records of the company. It has also been submitted that the submissions made by the domestic industry on this issue is clearly without any factual evidence as regards Chinese demand or global demand, thus issue of capacity addition is being stressed out of proportion and is clearly the baseless fear or threat which is preventing the domestic industry from allowing the new shipper to be competitive and fair trade.

29. Concerning investigation on issue of source of funds used for expansion, it has been submitted that an extreme case of serious prejudice is being made out by the domestic industry against the operations of the company, as the allegations doubt the operations of the company which is one of the largest producers of the subject goods in China but at the same time is a responsible and a listed company at the Singapore Stock Exchange on the basis of which stringent regulations apply to the company both by the stock exchange and also by its own government.

30. Regarding issue of selling price and cost of production being artificially low due to significant state interference and support in cost of plants, technology, labour, investments and supply of the product, it has been submitted that there is no state interference as already been explained in the submissions.

31. On the issue of company making significant losses, it has been submitted that it should not be linked to allegations of dumping, as there may be certain business decisions and business risks due to which company may face losses during that period and also there is no intention of any management or its company to plan for the same.

32. On the issue of selling price in the Chinese market remaining constant for 18-21 months and no change of prices when Caprolactam prices increased, it has been submitted that information in this regard has been submitted.

33. On the issue of ocean freight, it has been submitted that until or unless there is a related party, which is not so in the instant case as regards the freight company is concerned, the Designated Authority in the normal case should accept the expenses for the same.

#### **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

34. The Designated Authority, as per para 8(2) of Annexure I of the AD Rules for the purpose of determination of Normal Value, proceeded with a presumption that any country that has been determined to be or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti dumping investigation by the Designated Authority or by the competent authority of any WTO member country during the three years period preceding the investigation is a non-market economic country. In the past three years WTO members such as EU and USA have treated China PR as a non-market economy country in anti-dumping investigations. In the instance case, China PR was proposed to be investigated as non-market economy Country.

35. The Authority sent Market Economy Treatment (MET) questionnaire and exporter's questionnaire to M/s. Junma Tyre Cord Co. Limited, China PR (New Shipper). They filed the response in support of their claim of market economy treatment and requested for determination of normal value on the basis of domestic sales of subject goods in their home market. In view of their claim of MET treatment, verification was carried out at the premises of the responding producer and exporter. The new shipper has claimed individual treatment on the grounds that they are operating under market economy condition irrespective of prevailing economy situation in the country without any direct or indirect State interference or influence in their business activity.

36. The Authority notes that para 7 of Annexure 1 of AD Rules provides that:

*"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin."*

37. Further Para 8 of Annexure 1 of the AD Rules (as amended) provides that:

- (1) *"8 (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph(3)*
- (2) *There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti dumping investigation by the Designated Authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economic country;*
- (3) *Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)."*

38. It is noted that the new shipper furnished information/evidence as mentioned in para 8(3) of Annexure 1 of AD Rules to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether

- a) the decision of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs,

barter trade and payment via compensation of debts; such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

- d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate;
- e) Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the Designated Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in this paragraph.

39. Detailed questions regarding ownership, management, control, determination of commercial and business policies and on financial situation etc. were addressed to the applicant. Responses filed by the new shipper were analyzed to determine whether the applicant exercised a degree of independence from the Chinese Government comparable to what would prevail in a market economy country. The Authority sought general and certain specific information with regard to the following parameters from the applicants:-

- Ownership details
- Shareholding patterns
- Information on promoter/holding company/companies
- Constituents of Board of Directors, their legal status and person/party being represented by them.
- Raw Material Inputs and Costs
- Production Facilities and Costs
- Loans and subsidies
- Barter Trade/ Counter Trade
- Profit Distribution
- Bankruptcy and property laws
- Exchange rates conversions

40. In order to examine whether there was any degree of State influence or interference over the allocation of resources and decisions of the applicant, whether directly or indirectly, the ownership pattern of the petitioner was examined. The claims/ counter claims made by the interested parties were taken into account and details in this respect were verified.

### **Ownership of the Company**

41. The Authority notes that \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 was changed to Jiangsu Junma Group Co. Ltd.

42. M/s Jun Ma Nylon was incorporated on 12.6.1998 (Registered Capital RMB \*\*\*) in which Junma Group held share holding of 20% in form of assets, labour union 71.96%, Mr. Chen Zufu 4.44% and Mr. Liu Zhenfeng 3.6%. Subsequently, on 24.7.1999 Jun Ma Group Co. transferred its entire interest (20%) in Jun Ma Nylon to

other existing shareholders. On 1.8.1999, there was change in capital structure and shareholding. The shareholding became as Labour Union (54.8%), Chen Zufu (8%), Liu Zhenfeng (8.2%), Yang Peixing (20%), Jiang Jianping (4.5%) and Liu Yaoxiang (4.5%). On July 2000, Jun Ma Nylon was converted into joint stock company with change of name to Zhangjiagang Junma Tyre Cord Co. Ltd. On 7.8.2002, the name was further changed to Junma Tyre Cord Co. Ltd. The labour union which was holding 54.8% of the shareholding was replaced as Buole.

43. On 12.12.2003, capital structure of the company was further changed (registered capital RMB \*\*\*) with shareholding as Buole (41%), Chen Zufu (6%), Liu Zhenfeng (6.1%), Yang Peixing (15%), Jiang Jianping (3.4%), Liu Yaoxiang (3.4%) and "S shares" (25.1%).

#### **The Role of Buole**

44. The labour union comprised 121 individuals who were mainly management and production staff of Jun Ma Group company and became employees of the Jun Ma Nylon. It was also explained that in Jun Ma Nylon, labour union held 71.96% of the shareholding and had contributed \*\*\* RMB in cash. The 20% shares were held by Jun Ma Group and had contributed in the form of assets. The shareholding of labour union was changed to 54.8%. The shareholding of the labour union which was held by 121 individuals was transferred and held by 53 individuals. Subsequently, the labour union become Buole, an investment company established by 50 of the 53 individuals. The exporter was asked to provide the Annual Reports of the Buole. In this regard, it was informed "there are not annual reports prepared by Buole, since it is a company only investing in JUNMA incorporated collectively by individual shareholders of JUNMA. The registration documents of Buole is registered as a 100% private company incorporated by individual shareholders. We also wish to clarify that the former name of Buole which was earlier known "Labor Union". When JUNMA was incorporated, since there were too many shareholders who were individual investors. Since the year 2002, "Labour Union" modified itself in being called "Buole". All the shareholders of Buole are individuals, without any State interference."

45. The Authority also notes that in 2004 and 2005, the bank loans of the exporter were guaranteed by 'Buole' Zhangjiagang Buole Investment Development Company Ltd. (ZBIDCL).

#### **Senior Management**

46. Concerning senior management, the Authority notes that Yang Peixing, Executive Chairman, Liu Yaoxiang, Executive Director, Liu Zhenfeng, Executive Director, Zhou Zhidan, Executive Director, Chen Zufu, Non-Executive Director and Jiang Yuda, Non-executive Director i.e. senior management of the company continued to be associated with the company from the beginning i.e. they were senior management in Jun Ma Group and before formation of the Jun Ma group.

#### **Jun Ma Group**

47. It has also been noted that Mr. Yang Renming and Mr. Xu Feng of the Supervisory Committee are employees of Jun Ma Group.

48. The Authority notes that 'Buole' which was earlier known as a labour union provided 72% of the capital at the time of establishment of the company and continued to play very important role in providing capital subsequently. The loan of the company has also been guaranteed by Buole' (Zhangjiagang Buole Investment Development Company Ltd.) (ZBIDCL). Though it has been explained that Buole is only investment company and only investing in Junma, however, no information and evidence has been provided about the source of funds of the Buole who was earlier known as labour union. In absence of any transparent and credible evidence indicating that the investment made by individuals, as has been claimed, the Authority is not in a position to accept the claim that it is only an investment company of individuals who provided the capital. It is also not clear how the Buole without any assets can provide guarantee to banks for the loans taken by the Junma Tyre Cord Co. Ltd. In view of the fact, that the senior management of the company continue to be associated and had not undergone any change with the claim of transformation from State-owned company to private company and as noted from the Annual Report, two officials who are employees of the Jun Ma Group are on supervisory committee of the company, the claim of the new shipper that company has transformed from State-owned company to private company in which there is no State interference cannot be accepted. The company appears to be in state of transformation. The investment and guarantee of the loan by the Buole (erstwhile labour union) in non-transparent manner, the continuation of the senior management even after claim of transformation to the private company indicates that the new shipper is still working under the non-market conditions as significant State interference concerning decisions regarding investment and prices of the company cannot be ruled out. Therefore, the Authority holds that the new shipper has failed to rebut the presumption of non-market economy as per para 8(3) of Annexure 1 of the Anti-dumping Rules.

#### **E. METHODOLOGY FOR CALCULATION OF DUMPING MARGIN**

##### **E.1 Normal Value**

49. The new shipper has provided transaction-wise details of home sales made during the period of investigation. To ascertain the type of home sales comparable to the export sales, the company was asked to provide the details of coding system used by the company. It was explained that the coding system refer to type of fabric, denier and type of sale (domestic and export). It was noticed that in the invoices of the domestic sales more than 100 codes have been used. The exporter was asked to explain the meaning of different codes and their classification. In this regard, no reasonable explanation has been provided, hence it was not possible to ascertain the type of the product in the home sales as comparable to the export sales. However, in view of the fact that new shipper has failed to rebut the presumption of the non-market economy, so, the normal value cannot be determined as per the principles set out in para 1 to 6 of Annexure 1. Therefore, the normal value has been determined by method 'on any other reasonable basis' as per para 7 of the said Annexure.

50. The normal value has been constructed by adopting the methodology used during the original investigations. For construction, the price of Caprolactum prevalent during the period of investigation based on average ICIS LOR prices for China PR has been adopted. It has been seen that by adopting new shipper's Caprolactum procurement prices (inclusive of VAT and anti-dumping duty, where applicable), the final price exceeds that claimed by the domestic industry. The conversion cost adopted at the time of original investigation has been adopted by allowing a profit margin of 5%. Accordingly, the Constructed Normal Value (CNV) of

Grey has been restricted to the claim of domestic industry. In case of Dipped Fabric, the comparative price increase based on the prices prevalent at the time of original investigation vis-à-vis present have been allowed.

51. As indicated above the company has exported two types (Dipped and Greige) of NTCF to India during the period of investigation. Based on the methodology explained above type wise the normal values for these types of NTCF have been determined as under:

| Sl. No. | Description | Normal Value (US\$ per Kg.) |
|---------|-------------|-----------------------------|
| 1.      | NTCF Dipped | ***                         |
| 2.      | NTCF Greige | ***                         |

## E.2 EXPORT PRICE

52. In response to the questionnaire, the exporter has furnished invoice-wise/type-wise details of exports made to India during the period of investigation in Appendix-2. The information provided by the exporter has been verified from the original records. Exports to India have been made at CIF basis. The exporter has claimed adjustments on account of expenses for internal freight, international freight, international insurance, commission. The ex-factory export price has been calculated after taking into account the verified data regarding adjustments. The type wise ex factory export price of subject goods comes to :-

| Sl. No | Description | Export Price (US\$ per Kg.) |
|--------|-------------|-----------------------------|
| 1.     | NTCF Dipped | ***                         |
| 2.     | NTCF Greige | ***                         |

## E.3 DUMPING MARGIN

53. After determining dumping margins by considering above mentioned normal values and export prices for different types, the weighted dumping margin for Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF) has been determined. It has been found that the exporter has exported the subject goods below its Normal Value and the weighted average dumping margin has been determined as US\$ \*\*\*/kg.

## F. Recommendations of the Authority

54. After considering the foregoing the Authority concludes that

- Export price of Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF) produced and exported to India by M/s Junma Tyre Cord Co. Ltd., China PR is below its normal value during the period of investigation.
- The Authority, therefore, recommends that anti dumping duty INR 51.36 per kg. be imposed on imports of Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF) falling under Chapter 59 of the Custom Tariff Act, 1975 produced and exported to India by M/s Junma Tyre Cord Co. Ltd., China PR

55. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

R. GOPALAN, Designated Authority